DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI) : (a) to (d) A report from the State of Bihar has been called. The reply is awaited.

Regulation of Education in Private Schools

363. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact law for regulating education in private schools in different parts of the country; and

(b) if not, the reasons therefore?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (d) State/UT Govts. have been requested to send their views on the feasibility of enacting a central legislation in this respect since education is on concurrent list and school education is primarily the concern of State/UT Govts.

Action Plan for the Jakarta Asian Games

364. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have prepared an action plan to prepare and train the Indian team for the Asian Games to be held next year at Jakarta;

(b) if so, the steps taken/proposed to be taken in this regard; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) Yes, Sir. The Asian Games will be held from 6th to 20th December, 1998 at Bangkok (Thailand) and not next year at Jakarta.

(b) and (c) With view to fully prepare the Indian Teams in team events as well as individual events, the Government, the Sports Authority of India and National Federations of respective Games have jointly drawn up a Long Term Development Plan for each discipline to ensure that proper coaching is imparted to the sportspersons. In addition the sportspersons and teams have been exposed to intensive domestic and international competitions. Coaching camps have been held regularly in accordance with the calendar formulated in respect of each discipline. National Teams are being sent for regular participation in major international sports competitions such as Asian Championships, Commonwealth Championships, the World Cup Championships and other major international events.

The Government has also constituted a Discipline-wise Monitoring Committee headed by the Director General, Sports Authority of India (SAI) with representatives of the National Federation and outstanding sportspersons of the discipline concerned as Members to monitor the preparation periodically. The discipline-wise Monitoring Committee of each discipline has met twice and reviewed the preparations of 1998 Commonwealth Games as well as Asian Games. In addition, a National Monitoring Committee headed by the Minister of State for Sports has also been constituted with representatives of the National Federations and outstanding sportspersons as Members. The National Monitoring Committee met on 11.11.97 under the Chairmanship of then the MOS and reviewed the preparations. Besides, the preparation for both the Asian Games as well as the Commonwealth Games are reviewed regularly by the Government.

प्राथमिक शिक्षा के लिये विश्व बैंक सहायता

365. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा इस धनराशि का समुचित उपयोग किये जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा॰ मुरली मनोहर जोशी): (क) गत तीन वर्षों (1995-96 से 1997-98) के दौरान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी॰पी॰ई॰पी॰) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए

भारत सरकार तथा विश्व बैंक के मध्य 577.6 मिलियन यू०एस० डालर (लगभग 2010 करोड़ रु०) के लगभग सुलभ ऋण प्राप्त करने के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए। इसके अतिरिक्त, राज्य क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, जिसके लिए वर्ष 1993 में 165 मिलियन यू०एस० डालर (लगभग 577 करोड़ रु०) का सुलभ ऋण पहले ही दिया जा चुका था, के लिए 59.4 मिलियन यू०एस० डॉलर के (लगभग 220 करोड़ रु०) अनुपूरक वित्तपोषण के लिए भी एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया था। जि०प्रा०शि०का० की परियोजना अवधि 5-7 वर्ष है तथा विश्व बैंक द्वारा किया गया वास्तविक संवितरण एकमत पद्धति के अनुसार परियोजना पर किए गये व्यय पर आधारित है। गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए कुल 400.17 करोड़ रु० के लगभग तथा राज्य क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के लिए 458.06 करोड़ रु० के लगभग धनराशि का संवितरण किया है।

(ख) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय तथा विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला विवरण, विवरण-I में दिया गया है (**नीचे देखिए**)। गत तीन वर्षों के दौरान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) तथा राज्य क्षेत्र की उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त निधियों को श्रेणीवार उपयोगिता दर्शाने वाला विवरण विवरण-II में दिया गया है (**नीचे देखिए**)।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य कार्यान्वयन समितियों को निधियां जारी की जाती हैं तथा उनके द्वारा किया गया व्यय परियोजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा उनके वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में सम्मिलित गतिविधियों, जिनका अनुमोदन विस्तृत मूल्यांकन के पश्चात् किया गया, में निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। राज्य समितियों ने मैमोरैण्डम आफ एसोसिएशन एण्ड रूल्स और फाइनेंशियल रेगुलेशन को निधियों की समुचित उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रावधान के साथ पूर्णत: परिभाषित किया है। परियोजना के दायरे से बाहर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का आवधिक मूल्यांकन भी निरीक्षण मिशनों के दौरों, परियोजना प्रबंध सूचना प्रणाली तथा कार्यकारी समितियों की बैठकों द्वारा किया जाता है। राज्य समितियों की वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षा आंकड़ों सहित संसद में भी रखी जा रही है। निधियों के अनुचित उपयोग का कोई विशेष मामला भारत सरकार के समक्ष नहीं आया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा किया गया व्यय तथा विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला विवरण।

(रु० करोड़ों में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	व्यय	विश्व बैंक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति
1.	असम	44.96	40.01
2.	हरियाणा	49.77	44.77
3.	कर्नाटक	93.01	81.87
4.	केरल	44.00	40.81
5.	महाराष्ट्र	76.16	68.08
6.	तमिलनाडु	56.95	50.49
7.	हिमाचल प्रदेश	11.38	10.02
8.	उड़ीसा	9.20	8.07
9.	मध्य प्रदेश	26.03	23.91
10.	उत्तर प्रदेश	15.50	13.51
11.	बिहार	4.36	प्रतिपूर्ति के दावे विचाराधीन हैं।
12.	राष्ट्रीय घटक	18.73	18.63
	कुल	450.05	400.17

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा राज्य क्षेत्र की उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त निधियों का श्रेणीवार उपयोगिता दर्शाने वाला विवरण।

(रु० करोड़ों में)

क्र० सं०	श्रेणी	जिला प्रा.शि.का. के अन्तर्गत उपयोग की गई धनराशि	उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उपयोग की गई धनराशि
1.	सिविल कार्य	149.53	175.03
2.	उपस्कर, वाहन, पुस्तकें तथा सामग्री	56.43	26.53
3.	परामर्शी सेवाएं तथा कार्मिकों/ शिक्षकों का प्रशिक्षण	67.89	12.79
4.	कर्मचारियों का वेतन, कार्य एवं अनुरक्षण	126.32	243.71
	कुल	400.17	458.06